कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here



प्रिंट और गरीब जनता

- 19 वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक–चौराहों पर बेची जा रही थीं।
- अब गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में थे।
- 19 वीं सदी के आरंभ से ही सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुँच निःसंदेह बढ़ी।
- ये पुस्तकालय अकसर शहरों या कस्बों में होते थे, अथवा यदा–कदा संमन्न गाँवों में भी।
- स्थानीय अमीरों के लिये पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी।

जातिभेद और पुस्ताकें

- 19 वीं सदी के अंत से जाति–भेद के बारे में अनेक पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था।
- निम्न–जातीय आंदोलनों के मराठी–प्रणेता ज्योतिबा फुले थे।
- उन्होंने 1871 में अपनी पुस्तक 'गुलाम गिरी' में जाति–प्रथा के अत्याचारों पर लिखा।
- 20 वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा पर लेखन द्वारा जोरदार प्रहार किये।
- मद्रास के ई.वी. रामास्वामी नायकर ने जो कि पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई।
- अंबेडकर तथा पेरियार के लेखन पूरे भारत में पढ़े गये।
- स्थानीय विरोध आंदोलनों ने प्राचीन धर्मग्रन्थों की आलोचना की।
- इन्होने नये और न्यायपूर्ण समाज बनाने की मुहिम में पत्र–पत्रिकाएं और गुटके छापे।

मजदूर

- कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था।
- लेकिन मजदूरों को अपने तजुर्बो को ढंग से लिखने की शिक्षा ही नहीं मिली थी।
- 1938 में कानपुर के मिल–मजदूर काशीबाबा ने अनेक सवाल लिखकर और छाप कर जातीय व वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की।
- 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन 'सच्ची कविताऐं' नामक एक संग्रह में छापा गया।

LET'S LEARN TOGETHER
Download Mission Gyan App

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

- बंगलौर के सूती–मिल मजदूरों ने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरित होकर खुद को शिक्षित करने के लिये पुस्तकालय बनाये।
- समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया।
- उनकी मूल कोशिश यह थी कि–

(1) मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो।
(2) साक्षरता आये।
(3) उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे।

प्रिंट और प्रतिबंध

- 1798 से पहले ईस्ट–इंडिया कंपनी का शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था।
- मजेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरूआती कदम उन अंग्रेजों के खिलाफ ही उठे थे जो–
  - कम्पनी के कुशासन की आलोचना करते थे।
  - कम्पनी के हुक्परानों के काम को कोसने थे।
- कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे उनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक–एकाधिकार पर हमला न बोल दें।
- कलकत्ता सर्वोच्य न्यायालय ने 1820 के दशक तक 'प्रेस की आलादी' को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किये।
- कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया।
- अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबारों के संपादकों ने जब गुहार लगाई तो 1835 में गवर्नर जेनरल बंटिंक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिये राजी हो गया।
- फिर उदारवादी ब्रिटिश अफसर मेकॉले ने पहले वाली आजादियों को बहाल करते हुये नये कानून बनाये।
- कभी–कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिये मुश्किल हो जाता था।
- जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक–पद के लिये सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आलादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे।
- 'द फ्रेंड ऑफ इंडिया' ने सरकारी मदद लेने से इसलिये इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने को मजबूर होना पड़ेगा।

वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट

- 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया।
- कुछ अंग्रेजों ने 'देसी प्रेस' का मुँह बंद करने की मांग की।
- ज्यों–ज्यों यहाँ के भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर हो रहे थे, त्यों–त्यों ही ब्रिटिश सरकार कडे नियंत्रण पर विचार करने लगी।

LET'S LEARN TOGETHER
Download Mission Gyan App

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

- आइरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' लागू कर दिया गया।
- इस एक्अ से सरकार को प्रेस में छपी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया।
- अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी।
- बागी–रपट होने पर अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था।
- कई बार छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी।
- मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अकसर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से लगाया जाता है।
- ब्रिटिश प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र–पत्रिकाओं पर नजर रखता था।
- पहले विश्व युद्ध के दौरान 'भारतीय रक्षा नियम' के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी।
- इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की बजाय खुद को बंद कर देना उचित समझा।
- 1919 में रॉलेट एक्ट के समय भी विभिन्न अखबारों के खिलाफ भी सख्त जुर्माने तथा कार्यवाहियाँ की गई।
- द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत पर 'भारतीय रक्षा नियम' पारित किया गया, ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके।
- भारत छोडो आंदोलन की तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर की जाती थी।
- अगस्त–1942 में लगभग 90 अखबारों का दमन किया गया।
- गांधी जी ने 1922 में कहा–

वाणी की स्वतंत्रता.....

प्रेस की आजादी.....

सामुहिकता की आजादी.....।

स्वराज के लिये अनिवार्य है।

- भारत सरकार जनमत व्यक्त करने वाले इन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है।
- स्वराज, खिलाफत..... की लड़ाई से पहले इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है।
- दमन के बावजुद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते–फैलते गये।
- उन्होंने ब्रिटिश कुशासत की रिपोर्टिंग करना तथा साथ ही राष्ट्रवादी ताकतों की हौंसला–अफजाई जारी रखी।
- राष्ट्रवादियों को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ।
- जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में कालापानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई।
- नतीजे के तौर पर तिलक को 1908 में कैद कर लिया गया, परिणामस्वरूम पूरे भारत वर्ष में

Download Mission Gyan App

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

व्यापक विरोध हुये।

LET'S LEARN TOGETHER

Download Mission Gyan App

भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here